



छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, एक जवान शहीद

नेशनल डेस्क। छत्तीसगढ़ के देतेवाड़ा इलाके में नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है, जिसमें 6 सीआरपीएफ जवान घायल हैं। फायरिंग के दौरान नक्सलियों ने दूधखड़ा ब्लास्ट भी किया है। दो की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर रवाना कर दिया गया है। बताया जाता है कि सर्चिंग पर सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवान निकले थे। इसी दौरान एम्बुश लगाए नक्सलियों ने ब्लास्ट एवं फायरिंग की। 231वीं बटालियन का एक दल राज्य पुलिस के साथ जिले के अरनपुर में सड़क सुरक्षा ड्यूटी पर था, जब आईईडी ब्लास्ट हुआ और नक्सलियों ने गोशियां चलानी शुरू की। नक्सलियों ने पहले गोशियां बरसाईं, फिर जवानों द्वारा जवाबी कार्रवाई करने पर उन्होंने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईईडी धमाके और गोलीबारी में सीआरपीएफ के छह जवान घायल हो गए। घायल जवानों में एक की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। घटना दोपहर बाद लगभग 4.30 बजे पैरामिलिट्री फोर्स की कमाल पोस्ट के पास हुई। अधिकारी ने बताया कि घायल जवानों के हेलिकॉप्टर के जरिए उपचार के लिए ले जाया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में नौकरशाही को धमकाया जा रहा है : उमर

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को दावा किया कि जिन अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने का समर्थन किया था उन्हें अब 'डराया और धमकाया' जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने टि्वटर पर कहा कि मैं यह जानकर सकते हैं कि जिन अधिकारियों ने जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का समर्थन किया था, उनके प्रदर्शन मूल्यांकन को लेकर अब उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। गौरतलब है कि अब्दुल्ला चुनाव आयोग के राज्य विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ नहीं करवाने के फैसले को लेकर अपनी नाराजगी ज़ाहिर करते रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि कोई ईमानदार अधिकारी इन धमकियों से नहीं डरेगा। हमें व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और लाभों से आगे जाकर लोगों के हितों के लिए काम करना चाहिए, जो लोग ऐसी धमकियां दे रहे हैं वे राज्य में लंबे समय तक बने नहीं रह सकेंगे।

फोन कॉल को लेकर तिहाड़ जेल की याचिका पर अदालत ने मिशेल से जवाब मांगा



नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड बीबीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कि श्वन मिशेल और सीबीआई से सोमवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों की एक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में उस आदेश को चुनौती देने की मांग की गई है जिसके तहत जेल नियमों का उल्लंघन कर मिशेल को अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने जेल अधिकारियों की याचिका पर मिशेल और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि निचली अदालत ने संचार का अवैध और अनुचित विशेषाधिकार देते हुए किसी तथ्य और परिस्थिति पर विचार नहीं किया। सुनवाई अदालत ने जनवरी में मिशेल को अपने परिवार, दोस्तों और वकीलों को अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करने की इजाजत दे दी और उसे एक हफ्ते में 15 मिनट के लिये फोन करने की इजाजत है। तिहाड़ जेल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अजी सिंह ने कहा कि जेल नियमावली सिर्फ प्रति सप्ताह 10 मिनट तक फोन करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी 2017 के जेल अधिकारियों के परिपत्र के मुताबिक एक विदेशी नागरिक को सिर्फ अपने मूल देश में बात करने की ही अनुमति है। मिशेल मूल रूप से ब्रिटेन का रहने वाला है और जेल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वह अधिकतर इटली में अपने चकानूनी प्रतिनिधियों से संपर्क करता है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल को तय की है और कहा कि अगर मिशेल को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता तो उन्हें अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

सुनियोजित तरीके से रावी दरिया से लूटा जा रहा है रियासत का खजाना

कठुआ। खनन माफिया और खनन विभाग की मिलीभगत से बड़े ही सुनियोजित तरीके से रावी दरिया से रियासत का खजाना लूटा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने खनन पर रोक लगा रखी है बावजूद इसके प्रशासन के आदेशों को धत्ता बताते हुए खनन माफिया सूर्य बल्ले ही रियासत के खजाने को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सिर्फ रावी दरिया ही नहीं अन्य कई हिस्सों में भी अवैध खनन चोरी छिपे जारी है। जिसके चलते रावी दरिया की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही है। यही नहीं पंजाब के लोग भी विभागीय मिलीभगत से रात को हमारी हद में आकर खनन करने के बाद निकल लेते हैं। इसके लिए दरिया के बीबीबीच से मार्ग बनाया गया है जो सीधा पंजाब की हद से सीक जुड़ता है। इसपर आवाजाही खनन माफिया ही करता आ रहा है। दरअसल रियासती सरकार द्वारा वर्ष 2017 में एस.आर.ओ. 302 के तहत लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। परंतु जिला में साठ के करीब स्टोन क्रशरों में से मात्र 9 क्रशरों के पास ही इसका लाइसेंस है, उस हिसाब से राज्य भी नहीं दिखा रहा है। कई स्थानों पर तो पुरानी रियासती की स्लैब कर्मियों द्वारा रखे गए प्राइवेट एजेंटों को दी गई है जो सुनियोजित तरीके से रियासत के राजस्व को भी चूना लगा रहे हैं। कई स्थानों पर क्रशरों से भी माल धुंधड़ा बेचा जा रहा है।

क्रांति समय

हैदराबाद।

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एवं टीआरएस नेता विनोद कुमार उन प्रत्याशियों में शामिल हैं जिन्होंने तेलंगाना में 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। ओवैसी 2004 से लगातार तीन बार हैदराबाद सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं और चौथी बार अपना चुनावी भाग्य आजमाने जा रहे हैं। विनोद कुमार वर्तमान लोकसभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस)

के उप नेता हैं तथा उन्होंने करीमनगर से अपना पत्रा दाखिल किया है। इसी सीट से वह वर्तमान सांसद हैं। टीआरएस सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की सूची को हरी झंडी नहीं दी है। किंतु पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उन्हें इस सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। सत्तारूढ़ दल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह विनोद की उम्मीदवारी को समर्थन देंगे। ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस ए इतेहादुल मुसलमीन की इस मुस्लिम बहुल

सीट पर मजबूत स्थिति मानी जाती है। हैदराबाद से भाजपा एवं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की अभी तक घोषणा नहीं की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति ने पहले हैदराबाद सीट से मोहम्मद अजहरुद्दीन को उतारने के लिए पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व को सिफारिश भेजी थी। किंतु पार्टी सूत्रों के अनुसार पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान इसके लिए राजी नहीं हुए। टीआरएस एवं एआईएमआईएम के बीच तेलंगाना में लोकसभा चुनाव आपसी तालमेल के साथ लड़ने को लेकर समझ बनी है। टीआरएसएस सूत्रों

के अनुसार ओवैसी टीआरएस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। ओवैसी ने अपना पत्रा दाखिल करने के बाद ट्वीट किया, "हैदराबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत के वंचित, दमित और कमजोर तबके की आवाज रहा है। ईशाअल्लाह, यह आगे भी अपना काम करता रहेगा।" पिछले वर्ष दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम आठ



सीट पर लड़ी थी जिसमें सात पर सीटों पर टीआरएस का समर्थन वह विजयी हुई। उसने शेष 111 किया था।

दिल्ली: गठबंधन को लेकर आप नेता का बड़ा बयान, कांग्रेस ने बहुत देर कर दी



नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने लोकसभा चुनाव के लिये दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुये कहा है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, अब गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली की सभी सात सीटों के लिये पार्टी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की अब कोई संभावना नहीं है। पार्टी अपने उम्मीदवारों को वापस नहीं लेगी, इसलिये गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। राय ने कहा, "अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं कि कांग्रेस दिल्ली को लेकर गंभीर नहीं है। क्योंकि जिस राज्य में कांग्रेस गंभीर है वहां उनके प्रयास जारी हैं। इसीलिये रविवार को हमने अपना सातवां उम्मीदवार घोषित कर दिया।" उल्लेखनीय है कि छह सीटों के लिये आप के उम्मीदवार पहले ही घोषित किये जा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से अब बातचीत की कोई पहल किये जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की सभी सात सीटों के लिये 12 मई को छठे चरण में मतदात होगा। कांग्रेस में आप के साथ गठबंधन को लेकर आम राय कायम नहीं हो पाने के कारण पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित गठबंधन के लिये दोटक मना कर चुकी हैं वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन सहित अन्य नेता गठबंधन की वकालत करते हुये इस मामले में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कराये जाने की बात कह रहे हैं।

पंचतत्व में विलीन हुए मनोहर परिकर, बेटे ने दी मुखान्ति

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर परिकर का निधन रविवार को हुआ था। सोमवार को गोवा के ही मीरामार बीच पर राज कीय सम्मान के साथ परिकर का अंतिम संस्कार किया गया। परिकर के शव पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उन्हें गन सल्यूट भी दिया गया। मनोहर परिकर के बेटे ने उनको मुखान्ति दी। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गोवा की राज्यपाल मुदुला सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और कई अन्य नेता मौजूद रहे। लंबे समय से कैंसर



से जूझ रहे मनोहर परिकर का निधन रविवार रात को गोवा में हुआ था। सोमवार को अंतिम दर्शन के लिए उनका शव कला अकैडमी रखा गया। जहां से मीरामार बीच तक परिकर की आखिरी यात्रा निकाली गई। इस दौरान परिकर के दोनों बेटे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भी उनके दोनों बेटों से मुलाकात की और उन्हें ढाढस बंधाया। मनोहर परिकर की अंतिम यात्रा में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी भावुक हो गईं। उन्हें श्रद्धांजलि सभा में आंसू पोंछते देखा गया।

हनुमानजी के दर्शन कर प्रियंका गांधी ने शुरू की 'गंगा यात्रा'



प्रयागराज। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाढ़ा ने सोमवार को यहां हनुमान जी के दर्शन कर अपनी गंगा यात्रा शुरू कर दी। संगम तट पहुंचकर उन्होंने मां गंगा की पूजा की। वह मैन्या घाट से स्टीमर के जरिए वाराणसी के लिए रवाना हो गईं।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका इस सियासी यात्रा के जरिए पूर्वी यूपी में कई समीकरणों को एकसाथ साधने की कोशिश कर रही हैं। संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने देश के उत्थान और शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने यह भी कहा कि मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती। इसके बाद प्रियंका गांधी ने संगम तट पर मां गंगा की विधिपूर्वक पूजा की। इसके बाद वह बोट पर पहुंची और छात्रों के एक दल के साथ संवाद किया। प्रियंका ने हनुमान जी के दर्शन के साथ गंगा यात्रा की शुरुआत कर अपनी हिंदू विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश की। बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन अक्सर उन्हें ईसाई बताकर उन निशाना साधते रहते हैं। प्रियंका ने हनुमान जी की पूजा करके बीजेपी की इस धारणा को तोड़ा। यही नहीं पूरी यात्रा के दौरान वह कई मंदिरों में जाएंगी। प्रियंका गांधी रास्ते में मां विधवासीनी, शीतला माता, सीता जी और भगवान शिव के मंदिर भी जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है इस गंगा यात्रा के जरिए प्रियंका पूर्वी यूपी की अत्यंत पिछड़ी जातियों (EBC) को साधने की कोशिश करेंगी। उनकी नजर मछुआरों और निषादों पर है जो पिछले चुनावों में बीजेपी को वोट करते रहे हैं। पूरे सूबे में इन जातियों की आबादी करीब १२ फीसदी है। दरअसल, गोरखपुर उपचुनाव के परिणामों के बाद निषाद सूबे में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। निषादों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजपी भी जीतोड़ मेहनत कर रही है। योगी सरकार निषादराज की प्रतिमा बनवा रही है। अब निषादों को अपने साथ लाने के लिए प्रियंका उनके पास जा रही हैं। इसीलिए उन्होंने संगम के पास छतनाग की बजाय मैन्या से स्पेशल स्टीमर की सवारी कर यात्रा करेंगी। मैन्या निषादों द्वारा बसाया गया गांव है, जो संगम से १० किमी दूर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राज बब्बर कहते हैं कि यह गंगा मैया के आशीर्वाद से तट पर बसे उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास है जिन्हें सत्ताधरियों की सियासत कम प्राथमिकता देती है।

लोकसभा चुनाव: चिराग करेगे लोजपा उम्मीदवारों का चयन



बिहार/नयी दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान को सौंप दी है। लोजपा संसदीय बोर्ड की सोमवार को हुयी बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वसम्मति से बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया गया। लोजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है और सीटों के बंटवारे के तहत उसे बिहार में छह सीटें-हाजीपुर (सु), बैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई और नवादा आवंटित की गयी हैं। बोर्ड की बैठक के बाद चिराग पासवान ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर के निधन के कारण उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यु) 17-17 सीटों पर तथा लोजपा छह सीट पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में लोजपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके 6 उम्मीदवार विजयी हुए थे। लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और वह राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। पिछले चुनाव में लोजपा को मुंोर सीट दी गयी थी लेकिन इस बार यह सीट भाजपा को दी गयी है। और इस सीट के बदले उसे नवादा सीट मिली है। पिछले चुनाव में नवादा से भाजपा के गिरिराज सिंह जीते थे जो इस समय केन्द्रीय मंत्री हैं। और इस सीट के बदले उसे नवादा सीट मिली है। पिछले चुनाव में नवादा से भाजपा के गिरिराज सिंह जीते थे जो इस समय केन्द्रीय मंत्री हैं।

तेलंगाना: दो-तिहाई कांग्रेस विधायक हो सकते हैं टीआरएस में शामिल

हैदराबाद।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एक प्रमुख नेता ने सोमवार को संकेत दिया कि तेलंगाना में कांग्रेस के दो तिहाई विधायक उसके पक्ष में पाला बदलने की तैयार हैं। कांग्रेस के कुल 19 विधायकों में से आठ विधायक मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस में जाने को लेकर इस महीने की शुरुआत में अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। इससे आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर

तैयारियों में जुटी कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई हुई है। राव की पुत्री एवं निजामाबाद की सांसद के. कविता ने पीटीआई-भाषा से कहा, "जिस तरह से राज्य तरकी कर रहा है, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और तेलुगुदेशम के कई लोग, वे सभी टीआरएस में आने को इच्छुक हैं।" उन्होंने कहा, "जब संख्या दो तिहाई से अधिक (कुल क्षमता की) है, हम उन्हें प्रोत्साहित (पाला बदलने के लिए) कर रहे हैं। अन्यथा, किसी अकेले विधायक (को)... हम दलबदल के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे

हैं।" कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि टीआरएस उसके विधायकों को दलबदल के लिए उकसा रही है और वे राज्यपाल से मुलाकात करने के अलावा सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अभियान चलायेगा। उल्लेखनीय है कि 7 दिसम्बर, 2018 को संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में टीआरएस के खाते में 88 सीटें आई हैं। 119 सदस्यों



वाले इस सदन में कांग्रेस दूसरे पायदान पर है। भाजपा के पास महज एक सीट है।

कारवां-ए-अमन बस सेवा तीसरे सप्ताह भी स्थगित

श्रीनगर।

श्रीनगर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवां-ए-अमन बस सेवा लगातार तीसरे सप्ताह भी स्थगित कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि हमें जानकारी मिली है कि नियंत्रण रेखा के इस ओर भारतीय सैनिकों की अंतिम चौकी कमान के समीप पार पर मरम्मत का काम अभी चल रहा है जिसके कारण सीमा पार बस सेवा को तीसरे सप्ताह भी स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बस सेवा स्थगित होने की सूचना दे दी गयी है। उन्होंने बताया कि इस बस में जिन लोगों की सीटें बुक थी उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई। यात्रियों से कहा गया है कि बस सेवा शुरू होने पर उन्हें समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 04 मार्च को महाशिवरात्रि के कारण इस बस सेवा को स्थगित कर दिया गया। और यह भी बताया गया है कि उरी मुजफ्फराबाद रोड़ पर एक पुल की मरम्मत के कारण बस सेवा का संचालन नहीं हो सकेगा। यह बस सेवा सात अप्रैल 2005 से शुरू हुआ थी। भारत-पाकिस्तान के वर्ष 1947 में बंटवार के बाद बिछड़े सैकड़ों परिजनों को मिलाने के लिए इस बस सेवा को शुरू किया गया था। इस यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है बल्कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद प्यात्रा परमिट जारी किया जाता है। इस यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है बल्कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद प्यात्रा परमिट जारी किया जाता है।



संपादकीय

कट्टरपंथ का कहर

अपनी खूबसूरती व बेहतरीन क्रिकेट के लिए पहचान रखने वाले न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में हुए हमले ने पूरी दुनिया को स्तब्ध किया है। बेहतर शिक्षा व रोजगार के लिए दुनिया के देशों से आये लोगों की पहली पसंद न्यूजीलैंड व आस्ट्रेलिया रही है। मगर बीते काले शुक्रवार को जिस तरह श्वेत नस्लीय पहचान के एजेंडे के साथ मुस्लिमों को निशाना बनाया गया, वह दुर्भाग्यपूर्ण ही है। यह अच्छी बात है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्दन ने इसे देश के इतिहास का काला दिन बताते हुए आतंकवादी घटना बताया। मगर ब्रिटिश मूल के आस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रैंटन टैरेंट ने जिस तरह इस हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की श्वेत पहचान से जोड़ा, उसने पूरी दुनिया के प्रवासियों की चिंता को बढ़ा दिया। यह विडंबना ही है कि जो श्वेत नस्लवादी सोच द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद समाप्त हो गई थी, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल, वैश्वीकरण की विफलता और रोजगार पर आये संकट ने जिस तरह पश्चिमी देशों में संकीर्ण राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया उसकी परिणति नस्लवादी हिंसा के रूप में हो रही है। नि-संदेह इसके मूल में इस्लामिक आतंकवाद से उपजी प्रतिक्रिया भी है। जिस तरह यूरोपीय देशों में इस्लामिक आतकी संगठनों ने लगातार हमले किये, उससे उभजे असुरक्षाबोध ने श्वेत नस्लवाद को प्रश्रय दिया। दरअसल, पश्चिमी देशों में यह सोच विकसित हो रही है कि एशिया-अफ्रीका के लोगों खासकर मुस्लिमों के यहां बसने से कई तरह का सामाजिक व सांस्कृतिक चुनौतियां पैदा हुई हैं। नि-संदेह ऐसी सोच को प्रश्रय देने के पीछे राजनीतिक सक्रियता भी है। निःसंदेह भूगोल व समाज-शास्त्रीय दृष्टि से परे नफरत की यह भयावह सोच चिंता का कारण होना चाहिए। सारी दुनिया में नफरत और उन्माद का जो नया दौर शुरू हुआ है उसने सभ्य समाज को बड़ी चुनौती दी है। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए उभारी गई भावनाएं कालांतर में उग्र रूप में सामने आती हैं क्योंकि आम आदमी राजनेता जैसा दोहरा व्यवहार नहीं कर सकता। इन दक्षिणपंथी उग्रराष्ट्रवादी तत्वों का उदय अमेरिका में हुआ है और जर्मनी, फ्रांस और इटली में भी। घोर पूंजीवादी व्यवस्था की पक्षधर वैश्वीकरण की नीतियों ने जो आर्थिक विषमता के बीच दुनिया में बोये हैं, उससे उपजी गरीबी व आर्थिक विषमता का दोषी प्रवासियों को मान लिया गया है। ये वे लोग हैं, जिन्होंने अपना देश छोड़कर परायी जमीन पर मेहनत से अपने पैर जमाये हैं। उनकी सफलता और समृद्धि मूल देशवासियों को खटकती है। संकीर्ण राजनीति करने वाले राजनेताओं के इशारे पर यही सोच निरंतर उग्र होती जा रही है, जो यूरोपीय यूनियन से अलग होने की छटपटाहट में भी नजर आती है और मैक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी करने की डोनाल्ड ट्रंप की जिद में भी। मगर विडंबना है कि नस्लवादी सोच का शिकार निर्दोष लोगों को होना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की घटनाओं को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। श्वेत नस्लवाद के इस उदय को सामाजिक वैश्वीकरण की अवधारणा पर चोट के रूप में देखा जाना चाहिए। आज सद भाव, शांति और विवेक की पक्षधर ताकतों को मजबूत करने की जरूरत है।

मैनिफेस्टो में टैरेंट ने 2017 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक उज्बेक मुसलमान द्वारा भीड़ पर ट्रक चढ़ाने की घटना का जिक्र किया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। हमले में 11 साल की एक स्वीडिश बच्ची की मौत ने उसे झकझोर दिया था। यहां से जब वह फ्रांस पहुंचा तो शहरों और कस्बों में प्रवासियों की भीड़ देखकर हिंसा का निश्चय कर बैठा। प्रवासियों से उसका मतलब मुस्लिम शरणार्थियों और प्रवासियों से है।

आतंकवाद/ अवेश कुमार

न्यूजीलैंड जैसा देश, जहां हिंसा की घटना वर्षों से अपवाद रही हो, अचानक किसी मजहबी स्थल पर खून की होली खेली जाए, सरकार, पुलिस और आम नागरिक की क्या मानसिक दशा होगी, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। ‘‘ग्लोबल पीस इंडेक्स’’ यानी ‘‘नियंतण शांति सूचकांक’’ में न्यूजीलैंड 2017 एवं 2018 में दुनिया का दूसरा सबसे शांत देश माना गया। 2007 से 2016 के बीच यहां हत्याओं के मामले द्हाई अंक में भी नहीं थे। हां, 2017 में हत्या के 35 मामले सामने आए और पूरे देश में चंचा का विषय बने। ऐसे देश में 49 लोगों को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया। वह भी मजहब विशेष को निशाना बनाकर। हमलावर ने क्राइस्टर्चर्च के अल नूर मस्जिद और उपनगरीय इलाके लिनवुड मस्जिद में जुमे की नमाज का समय चुना ताकि एकांत्रित मुसलमानों को अधिक से अधिक संख्या में मार सकें। दुनिया भर में हो रहे आतंकवादी हमलों की प्रवृति के बीच इस हमले के पीछे का विचार इतना खतरनाक है कि अगर इसका विस्तार हो गया तो दुनिया का बड़ा भाग हिंसा-प्रतिहिंसा का शिकार हो जाएगा। इसे व्हाइट सुप्रीमैसी यानी त सबसे उच्च है, और उनका ही वर्चस्व होना चाहिए जैसी सोच की परिणति भी माना गया है। हमारे पास पूरी जानकारी मुख्य हमलावर 28 वर्षीय ब्रेंटन टैरेंट के सोशल मीडिया पोस्ट एवं उसके द्वारा बनाए गए मैनिफेस्टो पर आधारित है। हमलावर ने व्हाइट सुप्रीमेटिस्ट होने का संदेश दिया है पर इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया है, यह मूल बात है। जरा सोचिए, हमलावर ने हमले के पूर्व फेसबुक पर घोषणा कर दी थी कि हिंसा की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। उसने 17 मिनट तक फेसबुक पर लाइव किया। टैरेंट ने फेसबुक पोस्ट में-हमला वयों किया-शीर्षक के तहत लिखा है कि यह विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हजारों लोगों की मौत का बदला लेने के लिए है। उसके द्वारा बनाए मैनिफेस्टो का शीर्षक है- ग्रेट रिप्लेसमेंट यानी महान बदलाव। मैनिफेस्टो में टैरेंट ने 2017 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक उज्बेक मुसलमान द्वारा भीड़ पर ट्रक चढ़ाने की घटना का जिक्र किया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। हमले में 11 साल की एक स्वीडिश बच्ची की मौत ने उसे झकझोर दिया था। यहां से जब वह फ्रांस पहुंचा तो शहरों और कस्बों में प्रवासियों की भीड़ देखकर हिंसा का निश्चय कर बैठा। प्रवासियों से उसका मतलब मुस्लिम शरणार्थियों और प्रवासियों से है। हाल के वर्षों में जेहादी आतंकवादियों द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन..में हमलों ने उसके अंदर विचार पैदा किया कि मुसलमान तों पर विजय पाने के लक्ष्य से हिंसा कर रहे हैं। उसकी नजर में इसका जवाब तों की प्रतिहिंसा ही हो सकती है। इन विचारों से साफ हो जाता है कि उसके अंदर हिंसा द्वारा ेत सर्वोच्चता का नासमझा विचार पनपा तो जेहादी आतंकवादी हमलों के कारण। यह विचार किसी एक टैरेंट के अंदर पैदा नहीं हुआ होगा। ऑस्ट्रेलिया से

लेकर यूरोप, अमेरिका..सब जगह जेहादी आतंकवाद को लेकर मुसलमानों के बारे में ऐसी भावना व्यापक रूप से फैली है। शरणार्थियों एवं प्रवासियों पर छोटे-बड़े हमलों की घटनाएं चारों ओर हुई हैं। मुसलमानों को शरण देने का इन देशों में तीव्र विरोध हो रहा है। नई पीढ़ी के अंदर इस्लाम एवं ईसाइयत के संबंधों का इतिहास पढ़ने की प्रवृति बढ़ी है। इस पर पुस्तकें और वेबसाइट आ रही हैं। इनमें क्रूसेड्स यानी इस्लाम एवं ईसाइयत के बीच चले धर्मयुद्धों का इतिहास भी है। बताया जाता है कि जिन देशों में इस्लाम है, उनमें ज्यादातर में कभी ईसाइयत थी यानी इस्लाम ने हिंसा और मारकाट से इस्लाम का फैलाव किया है। न्यूजीलैंड में किसी को शरण मिलना अत्यंत आसान है। न्यूजीलैंड की करीब 49.5 लाख की आबादी में मुसलमानों की संख्या डेढ़ लाख के आसपास होगी। लेकिन इनकी बिल्कुल अलग मजहब आधारित जीवन शैली को एक वर्ग पचा नहीं पाता। हमलावर के

का प्रयोग किया है। टिवटर हैंडल से एक फोटो टवीट की गई, जिसमें दिखी बटूक का इस्तेमाल हमले में किया गया। इस पर एक संदेश था, जिसमें ऐसे लोगों के नाम लिखे थे, जिन्होंने नस्ल और मजहब के नाम पर लोगों को मारा था। उसके विचारों और तौर-तरीकों से आप इको फासिस्ट का मतलब समझ सकते हैं। यह निश्चय ही खतरनाक विचार है, जिसको आगे बढ़ने से पहले हर हाल में रोका जाना चाहिए किंतु जब तक जेहादी विचारधारा पर आधारित आतंकवाद खत्म नहीं होगा, पश्चिमी यूरोप एवं अन्य जगह रहने वाला मुस्लिम समुदाय अपने मजहबी कर्मकांड का पालन करते हुए भी अन्य धर्मावलंबियों के साथ घुलने-मिलने का स्वाभाविक व्यवहार नहीं करता इसे रोकना संभव नहीं है। नहीं रु का तो यह दो मजहबों के बीच जगह-जगह हिंसक हमले और प्रतिहमले का कारण बन सकता है। यह एक नये किस्म का क्रूसेड्स होगा।



बेकल करते आंकड़े

बेरोजगारी/ रविशंकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 लोक सभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। किन्तु चुनाव के बाद की स्थितियां स्पष्ट करती हैं कि उनका रोजगार संबंधी वादा दूर-दूर तक पूरा नहीं हुआ है। अब जबकि उनका कार्यकाल खत्म होने को है, तो उनसे लोग रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी, 2019 में बेरोजगारी दर 7.2 फीसद पहुंच गई। यह सितम्बर 2016 के बाद की सबसे ज्यादा है। पिछले साल सितम्बर में यह आंकड़ा 5.9 फीसदी था। रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पिछले साल 40.6 करोड़ लोग नौकरी कर रहे थे, वहीं इस साल फरवरी में यह आंकड़ा केवल 40 करोड़ रह गया। इस हिसाब से 2018 और 2019 के बीच करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इन आंकड़ों को सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले बेरोजगारी के आंकड़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जाता है। ऐसे में चुनाव से पहले बेरोजगारी दर में ऐसी वृद्धि मोदी के लिए चिंता का सबब बनने वाली है। हालांकि सरकार बेरोजगारी की अपने स्तर पर आंकड़ा जारी करती है, और सरकार ने बार-बार कहा है कि बेरोजगारी दर मापने के पुराने मापदंड में बदलाव की जरूरत है, लेकिन हाल में मोदी सरकार पर बेरोजगारी के आंकड़े को छुपाने का भी आरोप लग चुका है। रोजगार के आंकड़े को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन के दो अधिकारियों ने अपना इस्तीफा त्क दे दिया था। जिस सरकारी आंकड़े को उन्होंने छुपाने कोशिश की थी, उसमें खुलासा किया था कि बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर को छूते हुए 6.1 फीसद पर पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा नेशनल सैपल सर्वे ऑफिस के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे से सामने आया था। इसे लेकर मोदी सरकार चोतफांा फिर गई थी। एनएसएसओ की यह रिपोर्ट ही अकेले नहीं, बल्कि किसानों की आत्महत्या,

एनएसएसओ वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट, कृषि मजदूरी डेटा, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जातीय आंकड़े, राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण रिपोर्ट और विदेशी निवेश के आंकड़ों को भी मोदी सरकार जनता के सामने नहीं लाई। उसे डर है कि कहीं ये आंकड़े सार्वजनिक हो गए, तो विपक्ष को उसके खिलाफ और मुद्दे मिल जाएंगे। वह उसके खिलाफ हमलावर हो जाएगा। 2014 के आम चुनाव में रोजगार बढ़ा मुद्दा था। अब एक बार फिर बेरोजगारी पर कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जो चुनाव में मोदी के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि अपनी तमाम उपलब्धियों के बीच बड़ी चालाकी से मोदी सरकार रोजगार सृजन के ‘‘कमजोर आंकड़ों’’ को ढ़कने में सफल रही है। संसद में कई बार पीएम मोदी ने रोजगार के कई ऐसे आंकड़े पेश कर बताने कि कोशिश की उनके कार्यकाल में लोगों को पर्याप्त रोजगार मुहैया करवाया गया है। फिर भी पहली मर्तबा नहीं है, जब किसी सरकारी रिपोर्ट में देश के अंदर बेरोजगारी की विकराल स्थिति सामने आई हो, बल्कि सबसे पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर कहा था कि ठीक नोटबंदी के बाद 2017 के शुरुआती चार महीनों में ही 15 लाख नौकरियां खत्म हो गई थीं। नोटबंदी का ज्यादा असर रजियल इस्टेट और कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। जाहिर है देश में रोजगार और बेरोजगारी की भीषण स्थिति है। अफसोस, प्रधानमंत्री अपने वादे पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। उल्टे उनके कार्यकाल में नौकरियां और कम हो गई जबकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्री डीगे हांकते नहीं थकते कि मुद्रा लोन की बढ़ती संख्या और ईपीएफओ के साथ नये



पंजीकरण बताते हैं कि नौकरियों में वृद्धि हुई है। चलो, उनकी बात सही मान भी ली जाए तो सवाल वहीं आकर ठहर जाता है कि नौकरियों में यदि वृद्धि हुई है, और नये काम के मौके बन रहे हैं, तो देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? ऐसे में लोक सभा चुनाव से ठीक पहले इन आंकड़ों विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। खैर, देश की राजव्यवस्था की इस दिशा में आज तक जिस प्रकार की प्रतिक्रिया रही है, वही सबसे बड़ी समस्या है। अर्थात सरकार ने कभी भी बेरोजगार के विषय को चुनौती के रूप में नहीं लिया। पिछले कई दशकों से यह सामान्य समस्या रही। आज जब इसने संकट का रूप लेना शुरू कर दिया है, तब केंद्र और राज्य सरकारें इस संकट से बचने का प्रयास आंकड़े के माध्यम से करने की कोशिश में हैं। अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो भारत के भविष्य पर गहरा अंधेरा छा सकता है।

भारत का तरजीही व्यापार दर्जा

वीरेंद्र कुमार पैन्थूली सामाजिक कार्यकर्ता

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पहुंचने में सड़क परिवहन और उससे जुड़ा मूलभूत ढांचा महत्वपूर्ण है। इसमें सड़क तथा सेतु जैसे मूलभूत ढांचों को जलवायु बदलाव के क़ुप्रभावों से बचाने और उनके अनुकूलन पर काम करने का आह्वान भी किया गया है। निस्संदेह मौसमी आपदाओं को झेलने में समर्थ सड़कें राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों को आसान बना देती हैं। आज धरा का बढ़ता तापमान सड़कों पर भी असर

डाल रहा है। पिछलते हिमनद के साथ-साथ पिघलती सड़कों के प्रति भी सचेत किया गया है। ऐसा करना सामयिक भी है। विश्व में अधिकांश पक्की सड़कें जो ऐसकाल्ट या कोलतार से ही बनती रही हैं, तेज गर्मी में पिघलने लगती हैं। जिन ध्रुवीय प्रदेशों में वाहन परिचालन बर्फ की सड़कों पर होता है, वहां तापमान बढ़ने से बर्फ की सड़कें पिघलने लगती हैं। अर्थात हमें सड़कों का संयोजन कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़ों, कहीं सागर तटों, कहीं दलदली इलाकों और कहीं सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र में अलग-अलग रणनीति से करना होगा। हर कोई चाहता है कि

उसके आवागमन की राह बारहमासी हो। इस राह में कई चुनौतियां भी हैं। अब सड़कों की डिजाइन और सामग्री चयन के संदर्भ में पुराने आंकड़े उन्ने मददगार नहीं हैं। जलवायु बदलाव के हंगामे के बीच पुरानी सड़कों के आस-पास का भी मौसम वैसा नहीं रह गया है, जैसा उनके बनने के समय था। अतः पुरानी सड़कों को भी बारहमासी बनाने के लिए उसी तरह काम किए जाने की जरूरत है, जैसे हम भूकंपरोधी भवनों को रिट्रोफिटिंग कर भूकंप सहने लायक बनाते हैं। साथ ही, सेतुओं को भी हर मौसम में काम लायक बनाना है। चूंकि नदियां अपनी

राह बदल रही हैं, इसलिए कई बार पुल या उन तक पहुंच की सड़कों को नुल सिरे से बनाने की आवश्यकता हो जाती है। बारहमासी सड़क एक ही तरह की सामग्रियों से ही बने, यह भी जरूरी नहीं है। सड़क निर्माण स्थानीय उपलब्धता के हिसाब से अलग-अलग सामग्रियों से ऐसी सड़कें बन सकती हैं, वैसे ही अलग-अलग चौड़ाइयों की सड़कें भी बारहमासी हो सकती हैं। चार-छह लेन की सड़कें ही बारहमासी

होंगी, ऐसा नहीं है। निस्संदेह पारम्परिक ज्ञान और पारम्परिक कच्चे माल के माध्यम से सैकड़ों साल पहले बनी कई सड़कें आज भी मौजूद होंगी। हमें अध्ययन करना होगा। वैज्ञानिक राय है कि बारहमासी सड़कों के नीचे प्लास्टर और कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। जाहिर है देश में रोजगार और बेरोजगारी की भीषण स्थिति है। अफसोस, प्रधानमंत्री अपने वादे पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। उल्टे उनके कार्यकाल में नौकरियां और कम हो गई जबकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्री डीगे हांकते नहीं थकते कि मुद्रा लोन की बढ़ती संख्या और ईपीएफओ के साथ नये

समस्याएं और न बढ़ें, जैव विविधता पर संकट न आए और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग हो, पर्यावरण हानि कम से कम हो। शोर कम हो। ईंधन की खपत कम हो, इत्यादि। विडंबना है कि जलवायु बदलाव के अनुकूल जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनके लिए हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। भूमिगत जलस्त्रोत प्रणालियां ध्वस्त की जा रही हैं। जैव विविधता के प्रति भी संवेदनशीलता नहीं बरती जाती है व निर्माण के दौरान कम से कम कार्बन उत्सर्जन करने

वाले ईंधन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वृक्षों, जैव विविधता, नदियों व भूमिगत जलस्त्रोतों के प्रति संवेदनहीनता व अनावश्यक मुवा हानि के साथ बनी सड़कें बड़े संकट को भी आमंत्रण दे सकती हैं। आज सड़क सामग्रियों से सड़कें जाम हो जाती हैं, वाहन फिसलते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वास्तव में हमें सड़क निर्माण को गंभीरता से लेना होगा। ऑल टाइम उपयोग की सड़कों पर काम करने की जरूरत है। सड़कों पर पर्याप्त रोशनी के लक्ष्यों पर तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)



ऑफिस
में कई बार हम कुछ ऐसा पहनकर चले जाते हैं जिससे हम उपहास या गॉसिपिंग का पात्र बन जाते हैं। शालीनता के साथ अगर आप ऑफिस में अपने आपको कैरी करती हैं तो आपको कपड़ों को लेकर कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आपके ड्रेसिंग सेंस की सब तारीफ करेंगे

ऑफिस में क्या पहनें... जरा ध्यान दें

हर चीज चाहे वो कपड़े ही क्यों न हों, समय और जगह के माकूल होने चाहिए, नहीं तो वो बुरे लगने लगते हैं। यह बात यूँ तो हर जगह लागू होती है, पर अगर आप वर्किंग वुमन या गर्ल हैं तो फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में कई बार हम कुछ ऐसा पहनकर चले जाते हैं जिससे हम उपहास या गॉसिपिंग का पात्र बन जाते हैं। शालीनता के साथ अगर आप ऑफिस में अपने आपको कैरी करती हैं तो आपको कपड़ों को लेकर कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आपके ड्रेसिंग सेंस की सब तारीफ करेंगे, सो अलग।

ट्राउजर, जीन्स में फोन पिन न करें

अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट जैसे फील्ड वर्क में हैं तो ट्राउजर, जीन्स आदि में फोन पिन करना ठीक भी है, लेकिन ऑफिस में यह स्टाइल सही नहीं है। यह देखने में बिल्कुल चाइल्डिश लगता है। मोबाइल फोन को या तो अपने पर्स में या फिर हाथ में ढंग से कैरी करें।

स्किन रिवीलिंग ड्रेस को ना

बहुत ज्यादा स्किन रिवीलिंग ड्रेस पहन कर भी ऑफिस में आना अच्छी बात नहीं है। ऑफिस में इस तरह की ड्रेस न केवल खराब लगती है, बल्कि छवि पर भी इसका खास असर पड़ता है।



शॉर्ट कपड़े न ही पहनें तो अच्छा है

ऑफिस में कोई भी ड्रेस पहनने के लिए कुछ नियम-कायदे होते हैं। ऐसे में आप उन्हें फॉलो न करके शॉर्ट कपड़े पहन कर अगर ऑफिस आती हैं तो एक तो यह ऑफिस डेकोरम के खिलाफ बात होगी, दूसरे आप बिना मतलब के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाएंगी। इसलिए शॉर्ट ड्रेसिस न ही पहनें तो ज्यादा सही रहेगा।

बहुत ज्यादा टाइट और पतला कपड़ा

बहुत-सी महिलाएं यह मानती हैं कि फिटिंग के कपड़े पहनने से एक कॉन्फिडेंस आता है, यह कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर आप ऑफिस में फिटिंग के कपड़े की जगह बिल्कुल ही टाइट फिटिंग और बेहद पतले स्टाफ के कपड़े पहन कर आती हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट बन जाएं, जो पॉजिटिव वे में तो कम पर, निगेटिव वे में ज्यादा होगा।

हार्ड हील्स पहन कर आना

माना कि हार्ड हील्स पहनना आपको पसंद है, लेकिन ऑफिस में ये परफेक्ट नहीं। हील्स आवाज बहुत करती हैं, जो ऑफिस में अन्य लोगों को काम करने में बाधा पहुंचा सकती हैं। इसलिए अगर आपको हील पहननी भी है तो प्लेट हील या फिर कम हील की सैंडल पहनें या फिर प्लेट स्टाइलिश स्लीपर पहनें, पर जो भी पहनें, वो आपकी ड्रेस के मुताबिक हो, यह जरूर देख लें।

ज्यादा चटकीले रंग के कपड़े

ऑफिस में सिम्पल और सोबर रंग के कपड़े पहनना ज्यादा सही रहता है। कुछ महिलाएं होती हैं, जो ऑफिस में बहुत ज्यादा कलरफुल और चटकीले रंग के कपड़े पहन कर आती हैं। उनका यह ड्रेसिंग सेंस न तो ऑफिस के लिहाज से अच्छा होता है और न ही लोग उनके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करते हैं। हां उल्टे, वो मजाक का पात्र जरूर बन जाती हैं।

नहीं दिखे स्पेगिटी की स्ट्रिप

अंडर समीज या स्पेगिटी की स्ट्रिप अगर बार-बार फिसल कर आपके कुर्ते आदि की बाहों के नीचे आती है तो यह बहुत ही इम्बेसिंग मुमैंट हो सकता है आपके लिए। इसलिए ऐसे कपड़े बिल्कुल भी न पहनें, जिनकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े पूरे ऑफिस में।

लिविंग रूम

को बनाएं जानदार

कपड़े प्रेस करने वाले आयरन में जंग लग जाती है, जिसे आप नमक के घोल से साफ कर सकती हैं।

लिविंग रूम में कई तरह के फूलों के गुलदस्ते भी रखें। गुलदस्ते के लिए आप कृत्रिम के साथ-साथ प्राकृतिक फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिविंग रूम को सजाने का यह आसान तरीका है। लिविंग रूम में आप अपनी दीवार के लिए सफेद और मटैलिक सिल्वर के कान्बोनेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं।



बड़े काम का नमक

अगर कांच के गिलास साफ करने हैं तो उन्हें नमक वाले पानी के घोल में दस मिनट के लिए भिगो कर रखें और फिर उन्हें नींबू और साफ पानी से धो लें। कपड़े प्रेस करने वाले आयरन में जंग लग जाती है, जिसे आप नमक के घोल से साफ कर सकती हैं। महीने में एक बार नमक के घोल से चांदी का सामान साफ करें। चांदी के गहनों को नमक वाले घोल में 15 मिनट के लिए भिगो कर बाद में साफ पानी से धो लें।



ट्रेंडी प्रिंटेड ब्लेजर

मौसम को देखते हुए ब्लेजर और ट्रेंड को देखते हुए प्रिंट। यदि इन दोनों चीजों को साथ मिलाया जाए, तो जो मसाला तैयार होगा, वही लेटेस्ट ट्रेंड होगा। डिजाइनर इसी वजह से प्रिंटेड ब्लेजर ला रहे हैं।

लार्ज प्रिंट

व्हाइट बैकग्राउंड के साथ यदि ब्ल्यू लार्ज प्रिंट आजमाया जाए, तो यह सभी को पसंद आएगा। बूटेदार प्रिंट इस मामले में सबसे ज्यादा चलन में है। जारा इंडिया पर इसकी कीमत 4790 रूपए है।

मोनो प्रिंटेड

यदि आपको मल्टीकलर प्रिंट पसंद नहीं, तो वर्कलेस पर इसे आजमाएं। ये कई डिजाइन्स में अवेलेबल हैं। कूज ऑनलाइन स्टोर पर इसकी प्राइस 945 रूपए है।



माना आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और चेहरे को हमेशा साफ रखना चाहिए, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर घंटे ही अपना चेहरा धोते रहें। दिन में चेहरे को दो बार धोना चेहरे को साफ रखने के लिए पर्याप्त है।

चेहरे की त्वचा पर एक झुर्री या फाइन लाइन क्या दिखी, महिलाएं परेशान हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई हमेशा जर्वा बना जो रहना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम योजना ऐसी बहुत-सी हस्तकर्मों या आदतों दोहराते हैं जिस वजह से हम बहुत हद तक खुद ही खुद को न्योता देते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही छोटी पर महत्वपूर्ण आदतों के बारे में, जो आप और हममें होती हैं, जिसका खामियाजा हमारी त्वचा को उठाना पड़ता है।

वजन कम करने की चाहत

आजकल तो वजन कम करने का एक ट्रेंड ही चल पड़ा है। कई बार तो कुछ महिलाएं अपना वजन इतना ज्यादा कम कर लेती हैं कि बाद में उन्हें शरीर को सही रखने के लिए वजन बढ़ाना पड़ता है। ऐसा करने से त्वचा अपनी कसावट खो देती है। जिस वजह से त्वचा लटकती नजर आती है और उसका कसावट कम हो जाता है।

बहुत ज्यादा मुंह धोना

माना आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और चेहरे को हमेशा साफ रखना चाहिए, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर घंटे ही अपना चेहरा धोते रहें। दिन में चेहरे को दो बार धोना चेहरे को साफ रखने के लिए पर्याप्त है। एक बात का ध्यान रखें कि बार-बार चेहरे को धोने से चेहरे की त्वचा में मौजूद प्राकृतिक तेल खत्म हो जाता है और त्वचा अपने आप रूखी हो जाती है। जिससे रिकलप्स पड़ने की आशंका रहती है

स्ट्रॉ से पेय पदार्थ पीना

आप इसे फैशन मानें या फिर कुछ और, पर अधिकतर महिलाएं सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि को पीने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग ही करती हैं, पर स्ट्रॉ का उपयोग करते वक्त उन्हें यह बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है कि ऐसा करने से होंठों के चारों ओर की त्वचा सिकुड़ जाती है और इससे होंठों के आसपास की त्वचा में झुर्रियों की आशंका होती है।

बढ़ती है आपकी उम्र

कॉन्टेक्ट लेंस पहनना

कॉन्टेक्ट लेंसेस का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए आया था, जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा पावर वाला चश्मा होता था, लेकिन आज मामला थोड़ा उल्टा है। आजकल बाजार में हर रंग के कॉन्टेक्ट लेंसेस मिलते हैं, जिन्हें अक्सर लड़कियां फैशन स्टेटमेंट के चलते कैरी करती हैं। हमेशा कॉन्टेक्ट लेंसेस का इस्तेमाल करने से आंखों को चोट भी पहुंच सकती है और आंखों के आसपास की त्वचा चूँकि नाजुक होती है तो झुर्रियां पड़ने की आशंका भी होती है।

आंखें चेक कराएं

यूँ तो कायदे से साल में एक से दो बार आंखों का चेकअप कराना बहुत ही जरूरी है, पर अधिकतर महिलाएं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ऐसे में आंखों में भ्रंशपन की समस्या हो सकती है और इस कारण आपकी खूबसूरती भी जाती रहेगी और दोनों भीलों के बीच झुर्रियों की समस्या भी हो सकती है, इसलिए समय पर नियमित रूप से चेकअप कराना बहुत फायदेमंद रहता है

ज्यादा ड्राइविंग से बचें

आपमें से अधिकतर महिलाएं ये सोचती होंगी कि कार में ड्राइविंग करते वक्त वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बची रहती हैं।

वूलन चैकड

इसे किसी भी तरह की रेगुलर ड्रेस के साथ आजमाया जा सकता है। बीकाइंड ब्रांड के इस ब्लेजर की प्राइस 1799 रूपए से शुरू है।

लेपर्ड डिटेल्स

आप यदि इसे किसी पार्टी में पहन रही हैं, तो लेपर्ड डिटेल्स को आजमा सकती हैं। साड़ी पर भी ये अच्छे लगते हैं। विवैशियस इन वॉग ब्रांड ब्लेजर की प्राइस 2200 रूपए है।

पिंक फ्लोरल

यदि आप फ्लोरल प्रिंट ही आजमाना चाहती हैं, तो पिंक फ्लोरल को आजमाइए। कूज ऑनलाइन स्टोर पर प्राइस 1185 रूपए है।

कैजुअल प्रिंटेड

सिम्पल और सॉबर ब्लेजर के लिहाज से कैजुअल प्रिंटेड ब्लेजर बेस्ट ऑप्शन है। इन्हें किसी भी मौके पर कैरी किया जा सकता है। स्ट्राइलटॉस पर प्राइस 1399 रूपए से शुरू है

ब्राइट होलोग्राफ

यदि आप कॉलर लेंस ब्लेजर पसंद करती हैं, तो यह ब्राइट ब्लेजर आपको पसंद आएगा। ग्लेम एंड लव्स ब्रांड के ब्लेजर की कीमत 1999 रूपए है।



बीडी न देने पर युवक को जान से मारने की धमकी

सूरत। सरथाणा योगी चौक समीप से पसार हो रहे बोलेरो चालक के पास बीडी मांगे जाने पर उसने इन्कार कर दिया जिससे दो बदमाशों ने उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी।

सरथाणा पुलिस सूत्रों के अनुसार कारमेज तहसील के खोजागांव में रहनेवाले चतुर

नरसिंहभाई माधर ड्राइविंग करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। चतुरभाई शुक्रवार देर रात योगी चौक समीप मानसरोवर सोसायटी के पास से बोलेरो गाड़ी लेकर पसार हो रहे थे। इस दौरान एकटीवा गाड़ी सं या जी.जे.05 एफबी 6901 पर आये दो अज्ञात युवकों ने चतुरभाई को रोक बीडी मांगी। हलाकि

चतुरभाई ने बीडी की बजाय त बाकु देने की बात कही जिससे दोनों आवेशित हो गये और गाड़ी पर पत्थर से तोड़फोड़ की। जिसके बाद दोनों ने चतुरभाई को जान से मारने की धमकी दी। घटना के संदर्भ में सरथाणा पुलिस शिकायत के आधार पर आगे की जांच कार्यवाही कर रही है।

एनसीपी ने गुजरात में कांग्रेस से 3 लोकसभा सीटें मांगी

अहमदाबाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने गुजरात में कांग्रेस से तीन लोकसभा सीटों की मांग की है। गुजरात में कांग्रेस और एनसीपी के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है। लेकिन एनसीपी ने नवसारी, पंचमहल और पोरबंदर लोकसभा सीटों की मांग की है। सूरत के लिंबायत

क्षेत्र में एनसीपी का स मेलन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत बोस्की समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयंत बोस्की ने कहा कि गुजरात में हमने कांग्रेस से तीन सीटों की डिमांड की है। हमें भरोसा है कि जब पूरे देश में महागठबंधन हो रहा है तो गुजरात में भी होना चाहिए।

आर्थिक तंगी से त्रस्त युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

सूरत। सूरत शहर के पांडेसर क्षेत्र में एक युवक ने आर्थिक तंगी से त्रस्त होकर घर में ही फांसी लगा लिया। जिससे ईलाज हेतु सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांडेसर क्षेत्र में रहनेवाला 48 वर्षीय श्याम बिगान प्रधान पत्नी और 20 वर्षीय पुत्र के साथ रहता था तथा मजदूरी काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था। पिछले कुछ दिन से नौकरी छुट जाने से वह विकट आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। जिससे तंग होकर रविवार सुबह श्याम बिगान ने घर में ही लोहे की हुक के साथ फंदा लगा लिया। परिजनो को घटना की जानकारी होने पर तात्कालिक श्याम को ईलाज हेतु नई सिविल हॉस्पिटल ले गये। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

पिछले तीन दिनों में ३४२१ संपत्तियां सील

एएमसी द्वारा बड़े डिफोल्टर्स गिरफ्तार नहीं होने से सवाल

१०० से १००० करोड़ या इसके ज्यादा संपत्ति टैक्स बाकी हो ऐसे डिफोल्टर्स विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही

अहमदाबाद। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शहर में संपत्ति टैक्स के बाकी डिफोल्टर्स विरुद्ध सीलिंग अभियान शुरू किया गया है। लेकिन इसमें छोटे डिफोल्टर्स विरुद्ध ही कार्रवाई हो रही होने से अब एएमसी प्रशासन की भूमिका और रवैये के विरुद्ध गंभीर सवाल उठाये जा रहे हैं क्योंकि १०० से १००० करोड़ रुपये या इसके ज्यादा संपत्ति टैक्स बाकी हो ऐसे बड़े डिफोल्टर्स विरुद्ध किसलिए कड़ी कार्रवाई नहीं होती है? पिछले तीन दिनों

में एएमसी प्रशासन ने बाकी संपत्ति टैक्स वसूली अभियान शहरभर में किया गया। सिर्फ तीन दिनों में प्रशासन ने कुल ३४२१ संपत्तियां सील की है। जिसकी वजह से छोटे डिफोल्टर्स में दहशत फैल गई दूसरी तरफ, बड़े डिफोल्टर्स एएमसी प्रशासन की कृपा से बेखौफ घूम रहे होने से नया विवाद पैदा हो गया है। शहर में सोमवार सुबह से शासकों की सीलिंग अभियान से डिफोल्टर्स सक्रिय हो गये हैं, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक बात है कि म्युनिसिपल

कॉर्पोरेशन की जाल में बड़े डिफोल्टर्स गिरफ्तार नहीं होते हैं। ऐसे बड़े डिफोल्टर्स की करीब १०० से १००० करोड़ रुपये की बाकी संपत्ति टैक्स की रकम प्रशासन के चोपडे में दर्ज होने के बावजूद भी इनके विरुद्ध क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं होती है ऐसे प्रश्न उठाये गये हैं। एएमसी प्रशासन चालू वर्ष २०१८-१९ के संपत्ति टैक्स के सुबह से शासकों की सीलिंग अभियान से डिफोल्टर्स सक्रिय हो गये हैं, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक बात है कि म्युनिसिपल

१४ दिन बाकी रहे फिर भी गत दिन तक म्युनिसिपल तिजोरी में ८०२ करोड़ आया था। म्युनिसिपल शासकों ने पिछले कई वर्ष से आय के अपने संशोधित टारगेट को प्राप्त करने में विफल रहे हो इसका सिर्फ कारण बड़े डिफोल्टर्स के प्रति अपनायी जाती कृपा की भावना है। गैरजिम्मेदार संपत्तियों में चल रही सीलिंग अभियान में भी छोटे व्यापारी-दुकानदारों को जैसे टारगेट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े डिफोल्टर्स लाखों रुपये की टैक्स चोरी करके भी सुरक्षित है।

ऑपरेटर के टेबल पर से आइडी-पासवर्ड लिया था

फर्जी लाइसेंस घोटाले में एजेंट और ऑपरेटर की गिरफ्तारी

२०१८ में क्रिसमस छुट्टी दौरान कुल ८४ फर्जी लाइसेंस इश्यू हुए थे : महेन्द्र उर्फ पाजी और राकेश पटनी गिरफ्तार

अहमदाबाद। अहमदाबाद आरटीओ ऑफिस में फर्जी लाइसेंस घोटाले में आरोपी एजेंट और ऑपरेटर की गिरफ्तारी होने से खलबली मच गई है। शहर के सुभाषब्रिज पर स्थित आरटीओ में वर्ष २०१८ में क्रिसमस की छुट्टी दौरान आरटीओ ऑफिस की सॉफ्टवेयर में पासवर्ड डालकर कुल ८४ बेकलोग करके लाइसेंस इश्यू किया गया था। यह घोटाले मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद के एजेंट तथा पहले भूज आरटीओ में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करते

युवक को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी वजह से आरटीओ में और आरटीओ सर्कल में खलबली मच गई है। वर्ष-२०१८ में क्रिसमस की दो दिन की छुट्टी के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने अहमदाबाद आरटीओ में सारथी-४ सॉफ्टवेयर में पासवर्ड डालकर कुल ८४ बेकलोग एंटी द्वारा फर्जी लाइसेंस इश्यू किया गया था। इस मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में अपराध दर्ज किया गया था। क्राइम ब्रांच के पीआई केजी चौधरी और टीम आरटीओ में सीसीटीवी और टेक्नीकल

मदद से महेन्द्र उर्फ पाजी यादव (भरवाड, निवासी-हिलव्यू रेसिडेन्सी, भूज) और राकेश पटनी (निवासी-बोरडीवडनगर सोसाइटी, सरसपुर) को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लेपटोप और मोबाइल फोन जब्त किया गया। आरोपी महेन्द्र २०१० से २०१८ तक भूज आरटीओ में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर ड्यूटी करता था। जबकि राकेश अहमदाबाद आरटीओ में ६ वर्ष से एजेंट के तौर पर काम करता है। आरटीओ के काम लिए दोनों एक-दूसरे के

संपर्क में आये थे। जल्दी से पैसा कमाने के लिए राकेश पटनी ने छुट्टी के दिन का लाभ लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर के टेबल पर से सॉफ्टवेयर यूजर आइडी और पासवर्ड लिया था। राकेश वॉट्सएप द्वारा यूजर आइडी और पासवर्ड महेन्द्र को भेजा था। महेन्द्र ने इसके आधार पर सॉफ्टवेयर में गलत एंटी करके फर्जी लाइसेंस बनाया था। दोनों आरोपियों ने अहमदाबाद और राज्य के अन्य शहरों में स्थित आरटीओ ऑफिस में बेकलोग एंटी करके फर्जी लाइसेंस इश्यू किए जाने का सामने आया है।



क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए धोखाधड़ी के आरोपी।

विपक्ष के नेता परेश धानाणी के गढ़ में फिर से सेंध

अमरेली जिला सदस्य सहित १५० कांग्रेस के कार्यकर्ता के इस्तीफे

सहकारी नेता दीपक मालाणी को कांग्रेस से सस्पेंड करने पर १५० से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया



अहमदाबाद, १८ मार्च। गुजरात विधानसभा विपक्ष कांग्रेस के नेता परेश धानाणी के गढ़ अमरेली में फिर एक बार सेंध लगाया गया है।

सावरकुंडला तहसील के दो जिले पंचायत के सदस्य सहित १५० कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक साथ कांग्रेस से इस्तीफा देने से स्थानीय राजनीति में खलबली मच गई है। सहकारी नेता दीपक मालाणी को कांग्रेस से सस्पेंड करने पर कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव पहले ही कांग्रेस में एक के बाद एक सीनियर, नेताओं, और कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तीफा दिए जाने का सिलसिला जारी रहने से कांग्रेस की छवनी में खलबली मच गई।

स्थानीय सहकारी नेता दीपक मालाणी को कांग्रेस द्वारा सस्पेंड किए जाने पर स्थानीय स्तर पर यह निर्णय का भारी विरोध किया गया। अमरेली जिला पंचायत की विजपडी और आंबरडी सीट के सदस्य मालाभाई और रमीलाबहन मालाणी ने भी इस्तीफा दे दिया। सावरकुंडला के विधायक प्रताप दुधात के क्षेत्र में कांग्रेस को झटका लगा है। २०१९ के चुनाव समय ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे देने से राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

इसके लिए पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बैठक हुई थी इसमें यह निर्णय लिया गया था। आज नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्व की बैठक हुई इसमें कांग्रेस पार्टी के अपनी इच्छा से सस्पेंशन के निर्णय विरुद्ध भारी नाराजगी सामने आई। व्यक्ति की गई थी। कांग्रेस के स्थानीय सीनियरों और कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी व्यक्त करके पार्टी की इस प्रकार की नीति के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई और सामूहिक इस्तीफे देने का निर्णय लिया गया।



होली धुलेटी के त्यौहार के लिए बाजार में कलर औप पिचकारी आ गये हैं।